तरह से इन मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। इस मामले की शीघ्र जांच कर कंपनी मालिकों द्वारा किये जा रहे शोषण को रोका जाये।

(आठ) उड़ीसा के नवरंगपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के भूमिहीन कृषि कामगारों द्वारा, काम की तलाश में पलायन किया जाना रोकने के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री परसुराम माझी (नवरंगपुर) : उड़ीसा के नवरंगपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के आदिवासी जीविकोपार्जन के संकट का सामना कर रहे हैं। इनमें से अधिकतर रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों की ओर पलायन कर रहे हैं। उनके पलायन का प्रमुख सा कारण यह है कि कृषि श्रमिकों को वर्ष में मात्र 130 दिन काम मिलता है। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में तीन लाख कृषि श्रमिक और 2.5 लाख सीमान्त किसान हैं जिन्हें वर्ष में मुश्किल से 130 दिन काम मिलता है। इसके अतिरिक्त कोडा, प्राजा, भातरा, और गौंड सहित लगभग 50 प्रतिशत आदिवासी भूमिहीन कामगार है जिन्हें सरकार से भूमि का पट्टा नहीं मिला है। इसके साथ ही 40 प्रतिशत सीमान्त जनजातीय किसानों के पास एक एकड़ से भी कम भूमि है जिस पर वह कमजोर सिंचाई सुविधाओं के कारण कृषि नहीं कर सकते हैं। भूमि पर खेती न कर पाने में निर्धनता भी एक बड़ी बाधा है। इनमें से अधिकतर भूमिहीन है इसलिए उन्हें ऋण भी नहीं मिल पाता है।

इन परिस्थितियों को देखते हुए मैं यह मांग करता हूं कि खेती करने के लिए नवरंगपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के किसानों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता मंजूर की जाए। बैंको को चाहिए कि वे उन्हें कम ब्याज दर पर ऋण दे। भूमिहीन लोगों को पूरे वर्ष रोजगार देने के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना भी शुरू की जानी चाहिए। मैं भारत सरकार से इन जिलों के लोगों के पलायन को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने की मांग करता हूं।

(नौ) राजस्थान में शिक्षकों को सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत गैर-शिक्षण कार्यों से अलग रखे जाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री धनसिंह रावत (बांसवाड़ा) : महोदय, राजस्थान प्रदेश में सर्वशिक्षा अभियान में विद्यालयों के कक्षा कक्षों के निर्माण कार्यों की जिम्मेदारी उन विद्यालयों के अध्यापकों को सौंपने से विद्यालयों में अध्यापन का कार्य ठप्प सा हो गया है। अध्यापक निर्माण कार्य करने में व्यस्त रहते हैं। छात्रों के भविष्य की उन्हें चिंता नहीं है। उन्हें चिंता सिर्फ निर्माण कार्य की लगी रहती है। छात्रों को पढ़ाना उनके लिये प्राथमिकता नहीं रही हैं जिससे अध्ययनरत बालकों के भविष्य पर खतरा उत्पन्न हो गया है। अगर यही हालत रही तो देश में शिक्षा का ढांचा चरमरा जायेगा।

इस अत्यंत लोक महत्व के विषय पर माननीय मानव संसाधन मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर निर्माण कार्यों की एजेंसी पंचायती राज विभाग या अन्य किसी भी विभाग को बनाये जाने का आग्रह करता हूं।

(दस) अरुणाचल प्रदेश में सभी प्रशासनिक केन्द्रों को जोड़ते हुए सड़क संपर्क उपलब्ध कराने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री किरेन रिजीजू (अरुणाचल पश्चिम) : अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य होने के साथ–साथ रणनीतिक महत्व की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील स्थान पर स्थित है। यह पूर्व में बर्मा से, उत्तर में चीन से और पश्चिम में भूटान से घिरा हुआ है। इस राज्य में देश में सबसे कम सड़के हैं और इस राज्य का 70 प्रतिशत हिस्से में अभी भी सड़के नहीं हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों के स्थानीय लोगों को अभी भी विषम स्थितियों और कठिन भौगोलिक स्थितियों में अपने समीप के प्रशासनिक केन्द्रों तक पहुंचने के लिए अनेक दिनों तक पैदल चलना पड़ता है। राज्य लम्बे समय से सभी जिला मुख्यालयों को जोड़ने वाले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग के निर्माण की मांग कर रहा है।

मैं पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से अरुणाचल प्रदेश राज्य के सभी प्रशासनिक केन्द्रों को जोड़ने के लिए तत्काल कदम उठाने और सीमा सड़क संगठन की देखरेख वाले तेजपुर से तवांग तक के डिफेंस रोड को चौड़ा करने के कार्य को तत्काल पूरा करने हेतु आवश्यक धनराशि मुहैया कराने का अनुरोध करता हूं।

(ग्यारह) अर्द्ध-सैनिक बलों में रिक्त पड़े पदों को भरे जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री कृष्णा मुरारी मोघे (खरगौन) : महोदय, अर्ध सैनिक बलों में तनाव के करण बढ़ रही आत्महत्या और अपने अधिकारियों की हत्या के किस्से गत वर्षों में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन हादसों को रोकने के लिए केन्द्र सरकर द्वारा योग, साधना, लाफिंग थैरेपी और काउंसलिंग जैसे तरीके अपनाकर करोड़ो रुपये खर्च कर तनाव कम करने का प्रयास किया जा रहा है, परन्तु उसकी जड़ में छुपी समस्या पर ध्यान

नहीं दिया जा रहा। सैनिकों में मानसिक तनाव का मुख्य कारण जवानों की संख्या में कमी है। जवानों का अपने परिवारों से महीनों दूर रहने के कारण उनके मन में तनाव बढ़ रहा है। इस कारण वे या तो आत्महत्या कर लेते हैं या फिर अपने अधिकारियों को गोली का निशाना बना लेते हैं। इस तरह के हादसे वर्ष 2002 में 55, वर्ष 2003 में 64, वर्ष 2004 में 52, वर्ष 2005 में 65 और 2006 में 84 सामने आए हैं। अर्ध सैनिक बलों के जवानों की संख्या इतनी कम है कि उन्हें ज्यादा समय तक ड्यूटी करनी पड़ती है जिसके कारण प्रतिशोध की भावना उठ जाती है। सबसे ज्यादा रिक्त पद केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में है, जहां आज भी 28 हजार 4 सौ पद रिक्त पड़े हैं। सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी और असम राइफल इससे अछूता नहीं है। सभी में लगभग रात सात से नौ हजार तक पद रिक्त पड़े हैं। आज जब देश माओवाद और नक्सलवाद की समस्या से दिन प्रतिदिन जूझ रहा है ऐसे में सरकार को शीघ्रातिशीघ्र इन रिक्तियों को भरना चाहिए जिससे नक्सलवाद की समस्या से निजात पाने के साथ–साथ जवानों में बढ़ते तनाव की मानसिकता को रोका जा सके।

(बारह) केरल में रेल ऊपरि पुलों का कार्य शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी. करूणाकरन (कासरगोड) : मैं रेल मंत्री का ध्यान केरल राज्य में रेल ऊपरि पुलों के निर्माण की और आकृष्ट करना चाहूंगा। रेल ऊपरि पुलों का निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है तथा कुछ स्थानों पर निर्माण कार्य लंबित भी है। राष्ट्रीय राजमार्ग में भी कोई प्रगति नहीं है। इसमें लोगों को कठिनाई होती है। कई स्थानों पर राज्य सरकार ने कार्य पूरा कर दिया है, लेकिन रेल मंत्रालय ने कोई प्रगति नहीं की है तथा कार्य को पूरा करने के लिए मंत्रालय कोई पहल नहीं कर रहा है। इस प्रयोजनार्थ बजट में आबंटित निधियां भी इन कार्यों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं। रेल ऊपरि पुलों को पूरा करने में अत्यधिक विलम्ब से काफी क्षति हो सकती है तथा इस वजह से कई समपार (लेवल क्रॉसिंग) स्थानोंपर दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है।

अतः मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि इस संबंध में ठोस कदम उठाए जाएं तथा रेल ऊपरि पुलों का निर्माण कार्य समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जाए।

(तेरह) मेसर्स बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड द्वारा पश्चिम बंगाल में लाल कोठी और रानीगंज में धारित भूमि को राज्य सरकार को अंतरित करने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री बंसगोपाल चौधरी (आसनसोल) : मैं सभा का ध्यान एक काफी महत्वपूर्ण मामले की और आकृष्ट करना चाहूंगा। जुलाई, 2001 में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल में लालकोठी और रानीगंज में मैसर्स बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड के स्वामित्व वाली भूमि को बी.एस.सी.एल. के भूतपूर्व कर्मचारियों द्वारा गठित औद्योगिक कामगार सहकारी संस्था को सौंपने के लिए अनुरोध किया था। वर्ष 2003 में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोक सभा प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में इस आशय का आश्वासन भी दिया गया था।

पुनरुद्धार हेतु अद्यतन अर्थक्षम योजना सहित सभी आवश्यक कागजात् एवं दस्तावेज, जैसा कि वांछित था, भी इस वर्ष के बिल्कुल आरम्भ के समय पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए है। तथापि, इस प्रक्रिया में अत्यधिक विलम्ब हो रहा है। इसके साथ ही, प्रत्येक दिन बीतने के साथ बहुमूल्य संयंत्र एवं मशीनरी में जंग लग रहा है तथा ये बर्बाद हो रहे हैं। अतः, मैं केंद्र सरकार से आवश्यक कदम उठाने तथा भूमि का अंतरण राज्य सरकार को करने का अनुरोध करता हूं।

(चौदह) उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में शत-प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : महोदय, देश में विदेशी विश्वविद्यालयों के सौ फीसदी निवेश की मंजूरी सरकार ने देने की मंशा बना ली है। एक तरफ तो सरकार देश में पहले से ही संचालित फर्जी विश्वविद्यालयों पर लगाम लगाने में नाकाम रही है। जिससे डिग्री लेकर लाखों विद्यार्थी अपने लक्ष्यों को पाने में लगातार असफल हो रहे हैं, वहीं अब सौ फीसदी विदेशी महाविद्यालयों के निवेश की मंजूरी देश के हित में कतई नहीं हो सकती।

यहां यह सोचना है कि जहां पहले से ही देश में 144 विदेशी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और संस्थान चल रहे हैं जिसमें 117 अपने अपने देश के पाठयक्रमों का संचालन कर रहे हैं जिसके संचालन हेतु नियामक तंत्र अभी तक सरकार नहीं बना पाई है ऐसे में अब सौ फीसदी विदेशी विश्वविद्यालयों के निवेश की मंजूरी पर सरकार किस प्रकार देश के हित में कर पाएगी।

एक बात तो साफ है कि इस निवेश से गरीब और अमीर की खाई शिक्षा के क्षेत्र में अब अवश्य बढ़ेगी क्योंकि विदेशी विश्वविद्यालय व्यावसायिक नजरिए के तहत अपना कदम रखेंगी, ऐसे में दाखिले के लिए वह जो फीस वगैरह निर्धारित करेंगे वह वे अपने हितों को ध्यान में रखते हुए करेंगे जिससे गरीब आदमी इन विश्वविद्यालयों मे दाखिला लेने में अक्षम होगा।